

आत्मनरिभर कसिान एकीकृत वकिस योजना

चर्चा में क्योँ?

30 सलिनबर, 2021 को मुखयमंतरी योगी आदतियनाथ ने उत्तर प्रदेश के कसिानों को सशक्त बनाने के मशिन के तहत **आत्मनरिभर कसिान एकीकृत वकिस योजना** शुरु की। इस योजना के तहत 2,725 **कसिान उत्पादक संगठनों (FPO)** का गठन कया जाएगा, जसिसे 27.25 लाख शेरधारक कसिानों को सीधे लाभ होगा।

प्रमुख बडि

- कृषि विभाग के एक वरषिठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में कसिानों की आय बढाने के लयि प्रत्येक ब्लॉक में कम-से-कम एक FPO स्थापति करने का फ़ैसला कया है। चालू वतित वर्ष में राज्य सरकार ने इस योजना के लयि 100 करोड़ रुपए नरिधारति कयि हैं।
- कृषि विभाग ने आगे कहा कि सरकार अगले पाँच वर्षों के लयि प्रत्येक वर्ष 625 FPO स्थापति करेगी। केंद्र सरकार के संस्थानों के अलावा **उत्तर प्रदेश डायवर्सफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (DASP), हॉर्टिकल्चर फेडरेशन, योग्य FPO और स्वैच्छिक संगठन FPO** के गठन के लयि मलिकर काम करेगे। प्रत्येक FPO से औसतन 1.5 करोड़ रुपए के नविश की योजना है।
- 722.85 करोड़ रुपए की इस योजना से अगले पाँच वर्षों में **कसिान उत्पादक संगठनों (FPO)** से जुड़े 27 लाख से अधिक कसिानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- वर्तमान में प्रदेश के कुल 824 प्रखंडों में से 408 प्रखंडों में कुल 693 FPO का गठन कया गया है। औसतन लगभग 500 से 1,000 कसिान FPO से जुड़े हैं।
- FPO के माध्यम से कसिानों को उनकी उपज का सही दाम मलि सकेगा। योजना के तहत राज्य में कार्यरत FPO से जुड़े कसिानों को 5 लाख रुपए के ऋण पर चार प्रतशित की सब्सिडी मलिंगी। इस प्रकार कृषि वकिस से जुड़ी संस्थाएँ कृषि के बुनयादी ढाँचे को वकिसति करके खेती की लागत को कम करने और कसिानों की आय में वृद्धि करने में सकषम होंगी।
- योजना के तहत क्लस्टर आधारति कारोबारी संगठनों को पाँच वर्षों के लयि FPO बनाने हेतु पाँच लाख रुपए और नवगठति FPO को तीन साल के लयि छह लाख रुपए सालाना का करज़ दया जाएगा।
- फसल कटाई के बाद की बुनयादी सुवधियों के नरिमाण के लयि FPO को तीन प्रतशित की दर से ऋण प्रदान कया जाएगा, जसिसे FPO से जुड़े कम-से-कम 500 से 1,000 कसिानों को लाभ होगा और प्रत्येक वर्ष 3,000 नौकरियों का सृजन भी होगा।
- गौरतलब है कि अभी तक राज्य में उर्वरक, बीज एवं अन्य सुवधियाँ उपलब्ध कराने वाली **कृषि सहकारी समतियाँ (PACS)** मारजनि मनी के अभाव में **कृषि अधोसंरचना कोष (AIF)** की योजना का लाभ नहीं उठा पा रही थीं। अब राज्य के 1,500 PACS इस योजना से कसिानों को लाभान्वति कर सकेंगी।
- साथ ही सस्ते करज़ की उपलब्धता से राज्य की प्रत्येक PACS 20 लाख रुपए की परयोजना शुरु कर सकेंगी। PACS के ऐसे प्रोजेक्ट में राज्य सरकार 4 लाख रुपए मारजनि मनी के तौर पर देगी, जबकि AIF 16 लाख रुपए देगी। **इसकी ब्याज दर एक फीसदी होगी।**
- इस पैसे से PACS गोदाम बना सकेंगे, जसिसे कसिानों को लंबे समय तक अपनी उपज के भंडारण में मदद मलिंगी। साथ ही कृषि उत्पादन मंडी परषिद की 27 मंडियों में कटाई उपरांत भंडारण एवं प्रबंधन अधोसंरचना के नरिमाण के लयि 140 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। मंडी परषिद भी AIF से महज़ 3 फीसदी की ब्याज दर पर करज़ लेकर संसाधन बढा सकेगी।